संसदीय तानाषाही या सहभागी लोकतंत्र

तानाषाही हमेषा ही घातक होती है चाहे वह व्यक्ति की हो या ग्रुप की, अथवा संसदीय । लोकतंत्र और तानाषाही बिल्कुल दो विपरीत अवधारणाएँ हैं। तानाषाही मे शासन का संविधान होता है और लोकतंत्र मे संविधान का शासन । यदि कार्य पालिका, विधायिका तथा संविधान संषोधन एक ही इकाई के पास इकठ्ठा हो तो वह लोक तंत्र नही हो सकता। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी लोक स्वराज्य के पक्षधर थे और नेहरू जी तथा अम्बेडकर जी लोक स्वराज्य की जगह लोकतंत्र के । लोकतंत्र घोषित हुआ किन्तु गांधी जी के मरते ही लोकतंत्र का स्वरूप संसदीय तानाषाही का बना दिया गया। कार्यपालिका पर नियंत्रण, विधायिका के सम्पूर्ण तथा संविधान संषोधन तक के अधिकार संसद ने अपने पास सुरक्षित कर लिये । डा0 लोहिया जयप्रकाष तथा विनोबा से खतरा दिखता था। लोहिया जी से समझौता किया गया, जय प्रकाष को अन्देखा किया गया और विनोबा को सब तरह की सुविधाये देकर समाज सुधार की लाइन पकडा दी गई । यदि न्यायपालिका ने केषवानंद भारती प्रकरण मे असंवैधानिक तरीके से अंकुष न लगाया होता तो संविधान और संसद तो बिल्कुल ही एक दूसरे के पूरक बन गये थे। परिणाम हुआ कि संसद लगातार तानाषाही की दिषा मे बढती चली गई और समाज गुलाम होता गया। समाज की भौतिक प्रगति तो पर्याप्त हुई किन्तु नैतिक पतन भी उसी गति से बढता चला गया। राजनीतिज्ञ समाज मे भौतिक प्रगति की भूख पैदा करते रहे और ऐसी अनियंत्रित भूख समाज का नैतिक पतन बढाती रही। समाज के नैतिक पतन को बहाना बना बना कर संसद समाज के अनेक अधिकारो को अपने पास समेटती रही और संसद तथा समाज के बीच अधिकारों की ऐसी असमानता पैदा हुई कि वोट देने के अलावा समाज के पास कोई ऐसा अधिकार नही बचा जिसमे संसद को हस्तक्षेप का अधिकार न हो।

जय प्रकाष आंदोलन की विफलता के बाद लम्बे समय तक कोई मार्ग नही दिखता रहा। दूसरी ओर संसद भी लगातार तानाषाही की राह पर बढती चली गई। सारे देष मे गुलामी के विरूद्ध एक तडपन थी किन्तु संसदीय तानाषाही की जकडन इतनी ज्यादा थी कि तडपन की अभिव्यक्ति शून्यवत् थी। जो लोग इस गुलामी के विरूद्ध आवाज भी उठातें थे उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज से आगे नहीं बढ पाती थी। समाज के समक्ष संसदीय तानाषाही से मुक्ति के लिये चार ही मार्ग दिखते थे। 1. संसद मे जाकर संविधान संषोधन 2. जनमत जगाकर संसद को समझौता हेतु मजबूर करना 3. टयूनीषिया और मिश्र सरीखी अहिंसक क्रान्ति 4. लीबिया सरीखी हिंसक क्रान्ति । पहला प्रयोग जे पी आंदोलन के समय असफल हो चुका था। अहिंसक क्रान्ति स्वयं होती है, कभी की नही जाती। हिंसक क्रान्ति बहुत खतरनाक मार्ग है। अतः ऐसे समय मे अरविन्द केजरीवाल तथा अन्ना हजारे जी ने पहल करके संसद को समझौता हेतु मजबूर करने का मार्ग चुना और उसके लिये उन्होने भ्रष्टाचार जैसे लोकप्रिय मुद्दे को आधार बनाकर शुरूआत की। वास्तव मे अन्ना जी की टीम का वास्तविक उद्देष्य लोक पाल न होकर संसदीय तानाषाही से मुक्ति ही था किन्तु उन्होने शुरूआत लोकपाल से करना ठीक समझा। संसद और सरकार के लोग दो मार्ग मे बटे । एक गुट अन्ना आंदोलन की वास्तविक मंषा को भांपकर इन्हे कुचलना चाहता था तो दूसरा झुककर इनकी आंधी को निकलने देना चाहता था। दूसरे गुट की रणनीति कारगर रही। आंधी आई और निकल गई। संसद और सरकार को यह पता नही था कि अब आंदोलन का दूसरा चरण भी संभव है। दूसरी ओर टीम अन्ना ने भी समझ लिया कि सत्ता का चरित्र एक जैसा ही होता है। उसमे पक्ष और विपक्ष की लडाई वहीं तक होती है जिसमे दो भाई रामलीला मे राम और रावण की भूमिका मे युद्ध का ऐसा कला प्रदर्षन करें कि दर्षक मंत्र मुग्ध होकर अपना सब कुछ भूल जावे। रामलीला से प्राप्त धन लीला समाप्त हाते ही दोनो भाई मिलकर बांट लें। आंदोलन की हवा निकली देखकर तानाषाह संसद का व्यवहार कडा हुआ और आंदोलन अन्ना अपनी योजनानुसार दूसरे चरण मे प्रवेष कर गया।

टीम अन्ना को जरा भी उम्मीद नही थी कि संसद इतनी बडी भूल कर बैठेगी जो इस आंदोलन को पुनःजीवित कर दे। संसद के तानाषाही घमंड ने आनन फानन मे अन्ना जी की टीम के विरूद्ध अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया। अन्ना हजारे की टीम के खिलाफ शरद यादव ने जिस तरह भ्रष्टाचार के विरूद्ध टकराव को संसद के विरूद्ध टकराव बनाने के उद्देष्य से संसद मे भाषण दिया था वह पूरी तरह अमर्यादित था तथा भ्रष्टाचारी राजनेताओ की ढाल के रूप मे था। सांसदो के चेहरे देखकर लगता था कि अधिकांष सांसद शरद जी के कथन के पक्ष मे हैं। देष की जनता को महसूस हुआ कि ये नेता भले ही अलग अलग दलो के हो, भले ही एक दूसरे को कितना भी चोर डाकू कहकर झगडा करें किन्तु अन्ततोगत्वा हैं सब एक। किसी एक भी चोर पर जनता हमला करेगी तो सब एक जुट हो जावेगे।

जंतर मंतर पर चोर की दाढी मे तिनका शब्द पर जिस तरह पूरी संसद एक जुट हो रही है वह एक शुभ संकेत है। अब धीरे धीरे लोक और तंत्र के बीच ध्रुवीकरण होगा। मै पूरी तरह अरविन्द केजरीवाल के आक्षेपो का समर्थन भी करता हूँ और दुहराता भी हूँ । असल मे तो वर्तमान संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली ही प्रदूषित है जिसकी आड मे शरद यादव जैसे तानाषाह खुलेआम संसद मे जनता के विरूद्ध कुछ भी बोलने की हिम्मत करते हो तथा संसदीय लोकतंत्र के नाम पर संसद मे बैठे अपराधियों का अप्रत्यक्ष संरक्षण करते हो। किसी सभ्रान्त महिला को सांसद संसद मे परकटी महिला कहें तो भाषा संसदीय है और वह महिला संसद के बाहर उसे चोर की दाढी मे तिनका कहे तो संसद का अपमान हो गया। ऐसा तगता है कि मान अपमान की सारी ठेकेदारी संसद और सांसदो के पास ही एकत्रित है। किसी नागरिक के पास नही है। ऐसे माहौल मे अरविन्द केजरीवाल को पूरी हिम्मत बनाये रखने की जरूरत है कि वे कुछ भी अन्यथा या गलत नही कर रहे है। चोर को चोर कहने से अगर संसद की अवमानना हो भी जाती तो इसमे कोई बुराई नही है क्योकि हम जिस लोकतंत्र मे रह रहे है वह गुलाम लोकतंत्र है जिसमें संसद जनता को गुलाम बनाकर रखने मे ही अपनी सारी शक्ति लगा देती है।

हम जिस संसदीय लोकतंत्र मे रह रहे है वह जीवित लोगों का संगठन है जो लोकतंत्र के वास्तविक मालिक लोक को गुलाम बनाकर रखने के लिये तरह तरह के नाटक करता है। इसी नाटक प्रहसन के लिये एक किताब लिख दी गई है जिसका नाम संविधान है । संविधान का वास्तविक मतलब होता है कि वह तंत्र के अधिकतम और लोक के न्यूनतम अधिकारों की सीमा निष्चित करे तथा रक्षा करें।अगर आज व्यवस्था बिगड गई है तो आखिर क्या कारण है कि संविधान उसे रोक नही पाया है? साथ मे और तमाषा देखिये कि संसद जब चाहे अपनी सुविधानुसार संविधान मे मनमाना बदलाव भी कर सकती है। इसमे कोइ दो राय नही हो सकती कि तानाषाही की अपेक्षा संसदीय लोकतंत्र ज्यादा बेहतर विकल्प है लेकिन संसदीय लोकतत्र की अपेक्षा लोक स्वराज्य अर्थात सहभागी लोकतंत्र हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिये। आज का लोकतंत्र जो कि लोक नियंत्रित तंत्र होने की बजाय लोक नियुक्त तंत्र तक सीमित होता है इसमे लोक अपने ही बनाये तंत्र के हाथ गुलाम हो जाता है। लोक को अगर अपने द्वारा नियंत्रित तंत्र बनाना है तो उसे वर्तमान संसदीय प्रणाली को खारिज करना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नही है।

टीम अन्ना ने तो शरद यादव के संसद मे कहे वाक्य जनता को सुनाकर चोर की दाढी मे तिनका जैसे मुहावरे द्वारा एक माचिस की लौ मात्र फेकी थी। परिणाम दिखा कि संसद रूपी पेट्रोल स्वयं ही धू धू कर जलने लगा। शरद यादव लालू, मूलायम, फारूख अब्दुला सहित अनेक नेताओ ने संसद मे इतनी ज्यादा आग उगली कि उनका सारा तानाषाही पेट्रोल स्वयं जल गया और आंदोलन अन्ना को दुबारा फिर से जीवन दान मिल गया। बहुत अच्छा होता यदि संसद एक कठोर प्रस्ताव पास कर देती । और भी अधिक अच्छा होता यदि संसद कुछ दण्ड दे देती । ष्यदि ऐसा हुआ होता तो टीम अन्ना का तो काम ही बन जाता किन्तु पता नही किसकी सलाह पर उनके बढते कदम रूक गये।

स्वतंत्रता के बाद किसी ने पहली बार तानाषाही संसद के घोडे की लगाम छूने की हिम्मत की है। प्रष्न उठता है कि बार बार संसद या सांसद संसद सर्वोच्च का राग अलाप रहे है तो उन्हे बताना चाहिये कि संसद किसकी अपेक्षा स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास कर रही है । क्या संसद जनता से उपर है? क्या संसद न्यायपालिका के उपर है? क्या संसद राष्टपति के उपर है या फिर संसद संविधान के भी उपर है? बार बार यह सर्वोच्चता की दुहाई क्यों दी जा रही है? भारत मे जो संसदीय प्रजातंत्र काम कर रहा है उसमे

संसद सर्वोच्च नही हो सकती । हालांकि बडी चतुराई से उसने कुछ ऐसे अधिकार अपने पास रख लिये है जिसके कारण वह बार बार सर्वोच्चता की दुहाई देती जरूर है लेकिन वह सर्वोच्च नही है। लोक और तंत्र मे सर्वोच्च लोक होता है तंत्र नही । लोकप्रतिनिधि भला लोक से सर्वोच्च कैसे हो सकता है? अगर आप हमे अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते है और मेरे नाम पांच साल की एक पावर ऑफ अटार्नी लिख देते हैं कि मैं आपके नाम पर सारे फैसले ले सकता हूँ तो क्या मै आपसे अधिक ताकतवर हो सकता हूँ? क्या मुझे यह भूल जाना चाहिये कि मेरी ताकत आपकी रजामंदी मे निहित है? नियमतः ऐसा होना चाहिये लेकिन भारत मे लोकतंत्र के नाम पर जो स्वांग रचा जाता है उसमे लोकतंत्र का यही स्वरूप बन गया है।

भारत मे लोकतंत्र लोक नियंत्रित तंत्र की बजाय लोक नियुक्त तंत्र तक ही बनकर रह गया है। लोक की दषा इतनी कमजोर कर दी गई है कि वह अपने ही द्वारा नियुक्त तंत्र से सवाल नही पूछ सकता। उसके आचरण पर सवाल नही उठा सकता और अगर कोई अरविन्द केजरीवाल ऐसा करता है तो इसके लिये उसे कटघरे मे खडा कर दिया जाता है जैसे इस वक्त अन्ना हजारे और उनकी टीम को किया जा रहा है । जंतर मंतर पर एक दिवसीय अनषन के दौरान अन्ना जी की उपस्थिति मे भाई अरविन्द केजरीवाल तथा मनीष सिसौदिया ने जो कुछ कहा उसके लिये वे बधाई के पात्र है । जंतर मंतर पर हुआ क्या था? अरविन्द केजरीवाल या मनीष सिसौदिया ने तो पूरा मुहावरा भी नही कहा था। पूरा मुहावरा तो जनता ने कहा था। तो क्या अब हम भारत के लोग अपने ही द्वारा नियुक्त तंत्र के आचरण की चर्चा नही कर सकते।

अरविन्द केजरीवाल या अन्ना हजारे भारतीय संसद के बारे मे जो कुछ कह रहे है वह कम है । अरविन्द केजरीवाल न जाने किस डर से इस संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते रहते है। असल मे तो यह संसद ही चोर है। ऐसी चोर जिसने हमारे अधिकारों को बडी चालाकी से अपने पास सुरक्षित रख लिया है। नया कानून बनाने और संविधान मे सषोंधन के इसके अधिकार इसे अति शक्तिषाली बना देते है जिसके कारण यह तंत्र को मनमानी ढंग से संचालित करती है और लोक मूकदर्षक बना रहता है। अन्ना हजारे के आंदोलन से पहली बार ऐसा संभव हो रहा है कि जनता सांसदों को चोर कह रही है । वे जो हैं उनके बारे में उन्हे बता रही है।

संसदीय लोकतंत्र मे संसद कभी सर्वोच्च नही हो सकती । केषवानंद भारती बनाम भारत सरकार के फैसले इसका उदाहरण है कि न्यायपालिका जब चाहे संसद को उसकी चौहद्दी मे बांध सकती है । इसलिये संसद न्यायपालिका से सर्वोच्च होने का दावा नही कर सकती । राष्ट्रपति दोनो सदनो का महामहिम होता है इसलिये संसद राष्ट्रपति से सर्वोच्च होने का दावा नही कर सकती। संसद संविधान के तहत संचालित होती है इसलिये वह संविधान से उपर होने का दावा नही कर सकती । आखिर मे बचता है लोक। लोक इन समस्त लोगो से उपर होता है। लेकिन संसद व्यावहारिक अर्थों मे इसी लोक पर मालिकाना हक का दावा करके अपने आपको सर्वोच्च होने का दावा करती है। जब कि हकीकत यह है कि भारत का एक आम नागरिक पूरी संसद से उपर होता है क्योकि वह संसद को नियुक्त करता है। संसद उसे नियुक्त नही करती है।

प्रश्न यह भी है कि आगे का मार्ग क्या है और क्या होना चाहिये। तानाषाह संसद ने अपनी सीमाएँ स्पष्ट कर दी हैं कि वह सब कुछ बरदाष्त कर सकती है किन्तु अपने तानाषाही पावर मे कोई कटौती नही होने देगी। दूसरी ओर समाज के समक्ष भी सिर्फ एक ही विकल्प है । साठ पैसठ वर्षों के बाद अब हममे आपकी संसदीय तानाषाही को झेलने की स्थिति भी नही है। हमने संसद का अविष्वसनीय चेहरा देख लिया है कि थोडा सा दबाव पडते ही तो संसद अन्ना हजारे को खडे होकर सलामी देने जैसा ऐतिहासिक कदम उठाने तक झुक जाती है तो कुछ ही माह बाद उस व्यक्ति की कमजोरी महसूस होते ही मामूली सी बात पर उसके खिलाफ ऐतिहासिक अपमान जनक शब्दो का भी प्रयोग करने लगती है। यह स्पष्ट है कि इस बार निर्णायक परिणाम आना ही चाहिये। भारत की जनता तानाषाही से मुक्ति के लिये तैयार है। नेतृत्व की कमी अन्ना जी पूरी कर सकते है। अब दबाव बनाकर समझौते की उम्मीद व्यर्थ है। अब छिपकर लोकपाल से शुरूआत व्यर्थ है। अब इस संसद को मंदिर कहने का समय नही । यदि हमारा मंदिर भी तानाषाहों के कब्जे मे है तो हम उस मंदिर को जेलखाना और उस जेलखाने को मंदिर मानेंगे जिसमे तानाषाह हमारे लिये संघर्ष करने वाली टीम को बन्द करके रखे। संसदीय तानाषाही को सहभागी लोकतंत्र मे बदलने तक यह लडाई जारी रहनी चाहियें

इस समय दो प्रमुख समूह इस दिषा मे सक्रिय है वैसे तो रामदेव जी रविषंकर जी महाराज आदि भी सक्रिय है किन्तु उनके मुद्दे उतने स्पष्ट नही जितने टीम अन्ना अथवा लोक स्वराज्य मंच के है। गोविन्दाचार्य जी तो अब तक किस नाव की सवारी करे यह ही साफ नही कर पाये है। यदि सहभागी लोकतंत्र के लिये निर्णायक संघर्ष होगा तो ऐसे सब लोग अपने आप जुड जावेंगे। उपर लिखे दो समूहो मे एक है अरविन्द जी के नेतृत्व मे चलने वाला समूह जिसे अन्ना जी का भी आषीर्वाद प्राप्त है तथा दूसरा है सिद्धार्थ शर्मा बैगलूर के नेतृत्व मे काम कर रहा लोक स्वराज्य मंच। टीम अन्ना के पास बहुत बडी बिष्वसनीयता है, संगठन है, आधुनिक टेक्नीक है दूसरी ओर लोक स्वराज्य मंच के पास लम्बा अनुभव है, स्पष्ट मुद्दे है, गंभीर चिन्तन है। टीम अन्ना बार बार चरित्र की चर्चा करके विषय को भटका देती है जबकि लोक स्वराज्य मंच चरित्र की अपेक्षा नीतियों पर चर्चा को ज्यादा महत्व देता है। प्रष्न यह नही है कि कौन आगे आवे । चाहे मिलकर हो या अलग अलग किन्तु संघर्ष का संदेष समाज मे स्पष्ट जाना चाहिये, कि हम संसदीय तानाषाही को लोक स्वराज्य अर्थात सहभागी लोकतंत्र मे बदलना चाहते है। हमारी लडाई न लोकपाल की है न भ्रष्टाचार की। हमारी लडाई व्यक्तिगत चरित्र तक भी सीमित नही है। यह तो तब थी जब हम वर्तमान संसद का तानाषाही चेहरा साफ साफ नही देख पाये थे। इमानदार तानाषाह और अधिकार विहीन भ्रष्ट के बीच तानाषाह ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिये अब तो यही मार्ग दिखता है कि आगामी चुनावो मे संसदीय तानाषाही तथा सहभागी लोकतंत्र के बीच खुला मुकाबला हो। एक भी ऐसा व्यक्ति संसद मे न पहुच सके जिसने खुलेआम जनता के बीच यह घोषित न किया हो कि वह सहभागी लोकतंत्र के संविधान संषोधन मात्र तक ही सीमित है। तीन माह के अंदर ऐसा संषोधन पूरा करके वह त्यागपत्र दे देगा तथा पंख कतरने के बाद सबको नये चुनाव हेतु स्वतंत्र छोड देगा। मुझे तो स्पष्ट दिखता है कि यह संभव है। प्रष्न नेतृत्व का नहीं है । प्रष्न स्पष्टता का है। एक बार यदि धनबल बाहुबल और सत्ता बल को जनबल परास्त कर देगा तो लम्बे समय तक ये शक्तियॉ सर नहीं उठा सकेंगी। अरिवन्द केजरीवाल की टीम पहल करे या सिद्धार्थ शर्मा की टीम अथवा कोई और तीसरी टीम किन्तु दो हजार चौदह निर्णायक संघर्ष मे बदलना चाहिये जिसका नारा हो कि हमे सुराज्य नही, स्वराज्य चाहिये। ज्योही यह स्पष्ट स्वर किसी विष्वसनीय टीम से आयगा त्योंही वर्तमान संसद के भी बहुत लोग इस बात से सहमत नजर आयेंगे। शरद जी के विरूद्ध खेमे मे नीतिष कुमार दिखेंगे और मुलायम सिंह के विरूद्ध अखिलेष। यदि सोनिया राहुल ने सन पचहत्तर को दुहराना चाहा तो मनमोहन सिंह ही उसमे रोडा बन जायेंगे। अब न तो इंदिरा है न वैसा जमाना । उस समय कांग्रेस के चार लोगो ने बगावत की थी। इस बार तो लम्बी लाइन दिखेगी।

मेरा अपने सभी साथियो को सुझाव यह है कि हम अपने स्वतंत्र विचार रखते हुए भी चुनाव तक संसदीय तानाषाही से टकराव के मुद्दे पर अन्ना जी के नेतृत्व पर, अन्य राष्ट्रीय समस्याओ के समाधान मे मनमोहन सिंह के नेतृत्व पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ के समाधान मे पष्चिम के लोकतांत्रिक देषो के नेतृत्व पर अन्यो की अपेक्षा अधिक विष्वास व्यक्त करे। संसदीय तानाषाही हमारी एक जुटता को तोडने की कोषिष करेगी। हमे प्रयत्न करना चाहिये कि हमारी एक जुटता बनी रहे।

फिर भी साथ मे मेरा यह भी मत है कि निर्णायक संघर्ष के पूर्व वर्तमान संसद को यह अवसर दिया जाय कि वह स्वयं अपने तानाषाही स्वरूप को बदलने की पहल करे। वह लोकसंसद के प्रस्ताव पर सोचना शुरू करे। जिस संसद के पास कार्यपालिका का भी नियंत्रण हो और विधायिका का भी वही संसद संविधान संषोधन का भी अधिकार अपने ही पास रखे यह संसदीय तानाषाही नही तो और क्या है? सांसद मिलकर अपना वेतन भत्ता किसी भी सीमा तक बढाकर टैक्स रूप मे हमसे वसूल करें यह बिल्कुल गलत है । ग्राम सभाओ को प्रषासनिक

अधिकार मात्र दिये गये है। उन्हे विधायी अधिकार भी दीजिये। ऐसी ही तो चार पांच छोटी छोटी बातें लोक संसद प्रस्ताव मे है। संसद के किसी भी वर्तमान अधिकार मे कोई कटौती या नियंत्रण की बात लोक संसद के प्रस्ताव मे नही है और संविधान संषोधन का अधिकार वर्तमान संसद से हटाकर किसी अन्य इकाई को दिये बिना संसदीय तानाषाही शब्द मे से तानाषाही का कलंकित शब्द हटेगा नहीं। अब निर्णय आपको करना है कि आप संसदीय तानाषाही के वर्तमान स्वरूप पर ही अडिग है अथवा लोक संसद के प्रस्ताव पर समझौता करने को तैयार है अन्यथा तीसरा और अन्तिम विकल्प तो दो हजार चौदह है ही।

बंगाल की षेरनी ममता

कहावत है कि षेर की सवारी प्रारंभ में तो बहुत लाभदायक होती है किन्तु अन्त में सवार की जान लेकर ही उसका पेट भरता है। कांग्रेस पार्टी के साथ ममता बनर्जी का सम्बन्ध भी लगभग उसी दिषा में बढ़ रहा है। यह सच है कि बंगाल में तानाषाह बन चुके साम्यवाद से पिण्ड छुड़ाने का ममता बनर्जी के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। ममता ने बंगाल में साम्यवादी अत्याचारों का जिस तरह मुकाबला किया वह अब तक पूरी तरह प्रकाष में नहीं आया है। ममता बनर्जी ने जिस तरह नैतिकता की सारी सीमाएँ तोड़कर साम्यवाद से संघर्ष किया वह संघर्ष उसके लिये बंगाल की शेरनी कहे जाने के उपयुक्त ही है। साम्यवाद के पतन के लिये तीन स्थितियॉ एक साथ जुड़ गई थीं (1) साम्यवादी विचारों का नेतृत्व प्रकाष करात सरीखे अनुभव हीन के पास होना जिसने घमण्ड में आकर केन्द्र सरकार से नाता तोड़ लिया (2) बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में बुद्धदेव भट्टाचार्य सरीखे भले आदमी का होना (3) बंगाल की साम्यवादी सरकार का मुकाबला एक अत्यन्त तेज तर्रार चालाक महिला से होना। तीन स्थितियां एक जुट हुई तब बंगाल साम्यवाद से मुक्त हुआ।

ष्षेरनी ने केन्द्र सरकार को सवार के रूप में जोड़कर बंगाल की सत्ता पा ली है। अब षेरनी भूखी है और उसे अपने सवार के अलावा कोई अन्य दिखता नहीं। सवार रूपी केन्द्र सरकार चारों ओर छटपटा रही है। तानाषाह साम्यवाद के साथ कोई समझौता न बंगाल स्वीकार करेगा न ही देष। दूसरी ओर षेरनी ऐसा कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं जिसमें उसे सवार का कुछ न कुछ लहू पीने का अवसर नहीं मिलता हो। निराष सवार कातर दृष्टि से समाज के समक्ष गुहार लगा रहा है।

रेल मंत्रालय प्रकरण ने वह अवसर दे ही दिया जिससे ममता का समाधान निकलना षुरू हुआ। देष साम्यवाद की वापसी झेलने की स्थिति में नहीं है। साथ ही देष ममता का पेट भी नहीं भर सकता। ममता ने अपने स्वभाव अनुसार रस्सी को बहुत ज्यादा खींच दिया जिसके परिणाम स्वरूप दिनेष त्रिवेदी रूपी प्रहलाद साम्यवाद और ममता के बीच विकल्प के रूप में सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी बहुत ही सही कदमों से बढ़ रही है और ममता चाहे जितनी चालाकी कर ले किन्तु बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में दिनेष त्रिवेदी की स्थापना ममता रोक नहीं पायगी।

सम्पूर्ण भारत में ममता बनर्जी के विषय में भले ही अन्य कोई अनुमान न लगा पाया हो किन्तु मैंने यह अनुमान दो वर्ष पूर्व ही लगा लिया था तथा उक्त अनुमान की घोषणा भी कर दी थी। दिसम्बर दो हजार दस में सम्पन्न वार्षिक सम्मेलन में मैंने ममता बनर्जी के विषय में जो कहा था उसकी रिपोर्ट ज्ञानतत्व दो सौ पंद्रह जनवरी सोलह से इकतीस दो हजार ग्यारह के पृष्ट दस पर अंकित है जिसका संक्षिप्त इस प्रकार है (मेरा प्रस्ताव है कि हम दलगत राजनीति से उपर उठकर अच्छे लोगों के हाथ मजबूत करें चाहे वे किसी भी दल के क्यों न हों। मेरा सुझाव है कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, चिदम्बरम् नरेन्द्र मोदी, रमणसिंह, शान्ताकुमार, नितिष कुमार, षिवराज सिंह चौहान, बुद्धदेव भट्टाचार्य, अच्युतानन्दन, नवीन पटनायक, बाबूलाल मरान्डी जैसे अपेक्षाकृत अधिक अच्छे लोगों का मनोबल बढ़ावें तथा लालू प्रसाद, रामबिलास पासवान, अजीत जोगी, मायावती, मुलायम सिंह, षिबू सोरेन, जयललिता, करूणानिधि, ममता बनर्जी प्रकाष करात, स्वामी अग्निवेष जैसे अपेक्षाकृत अधिक बुरे लोगों का मनोबल गिरावें। इस प्रस्ताव पर गरमा गर्म बहस हुई। महाराष्ट्र के लोगों ने पृथ्वीराज चहवाण तथा ए0के0 एन्टोनी का नाम अच्छे लोगों की सूची में डालने की इच्छा व्यक्त की जिसे चर्चा के बाद मैंने मान लिया। कुछ लोगों ने ममता बनर्जी का नाम बुरे लोगों की सूची से हटाने की बात कहीं तो कुछ ने नक्सलवाद के प्रति उनकी नीति और विषेषकर नक्सलवादी रेल दुर्घटना में उनकी भूमिका को बिल्कुल गलत बताया। कुछ लोगों ने दिग्विजय सिंह का नाम बुरे लोगों की सूची में डालना चाहा तो मैंने स्पष्ट किया कि यघपि दिग्विजय सिंह उस सूची की दिषा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं किन्तु अब तक यह साफ नहीं है कि वे राहुल गांधी के इषारे पर उधर जा रहे हैं या दिग्विजय सिंह के इषारें पर राहुल गांधी गलत दिषा में जा रहे हैं। एक बात और है कि पंचायती राज की दिषा में दिग्विजय सिंह का रेकार्ड बहुत अच्छा रहा है। अतः इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं। इस प्रष्न पर चर्चा अधूरी रही।) इस तरह बंगाल चुनाव के पूर्व ही ममता बनर्जी के विषय में इतनी सटीक भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी। मेरे साथियों के आंषिक विरोध के बाद भी मैंने हमेषा ही यह बात दुहराई।

बंगाल के चुनाव हुए । साम्यवाद से पिण्ड छुडाने के लिये ममता का समर्थन समाज की मजबूरी थी। चुनावो के तत्काल बाद ही मैने बुद्धदेव जी भट्टाचार्य को सलाह दी थी कि वे साम्यवाद से तलाक लेकर कांग्रेस से समझौता कर ले तो शीघ्र ही वे हारी बाजी पलट सकते है किन्तु वे नही माने। पूरा देष बंगाल मे किसी नये चेहरे की तलाष मे था। ममता के ऐसे व्यवहार के बाद भी रेलमंत्री दिनेष त्रिवेदी ने जिस तरह का सौम्य व्यवहार बनाये रखा उससे तो हमे मेहरदीन और चंदगीराम के बीच की कुष्ती की याद आ जाती है जब मेहरदीन सरीखे ताकतवर घमंडी को एक बहुत ही कमजोर दिखने वाले शालीन चंदगीराम ने बडी आसानी से चित कर दिया था। इस प्रकरण मे भी दिनेष त्रिवेदी ने जिस कौषल से ममता बनर्जी को समाज की नजरो से गिराया वह घटना ऐतिहासिक ही तो मानी जायगी।

जहॉ तक रेल किराये का संबंध है तो लालू से ममता तक के आठ दस वर्षो मे रेल विभाग के साथ मनमाना बलात्कार किया गया। मैने तो कई बार कहा भी कि रेलवे का किराया एकबार मे दो गुना करके वह सारा धन नई रेल लाइनों के निर्माण मे लगा देना चाहिये। पिछले क्षेत्रो मे बहुत सुविधा हो जायगी। सडक मार्ग पर दबाव घट जायगा। पर्यावरण पर भी अच्छा प्रभाव पडेगा। किन्तु जनहित की अपेक्षा जनप्रिय बनने के लालच मे किसी ने एक न सुनी। अन्त मे ममता को जनता ने बताया कि यह जनता सब समझती है।

अब तक कुछ प्रदेषो के राजनैतिक भाग्य का निर्णय तो स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ मे रमणसिंह जी स्थायी दिख रहे है क्योकि जब तक अजीत जोगी कांग्रेस के चेहरे बने रहेंगे तब तक रमणसिंह जी को कोई खतरा नहीं। गुजरात मध्यप्रदेष, बिहार की भी राजनीति ठीक लाइन पर है उत्तर प्रदेष मे अखिलेष यादव से उम्मीद बंधी है कि वे माया मुलायम संस्कृति से यूपी को मुक्त कर लेगे। यदि ऐसा हुआ तो यू पी भी निपट जायगा। महाराष्ट मे पृथ्वीराज चौहान की परीक्षा बाकी है। उत्तराखंड मे भुवन चंद्र खंडूरी की भी बहुत प्रषंसा सुनी है। भारतीय जनता पार्टी के ही लोगो ने उन्हे विधायक पद से भी हरा दिया यह अलग बात है किन्तु खंडूरी जी इस सूची मे जुडने योग्य है। झारखंड मे बाबूलाल मरांडी को भी बढना चाहिये । तमिलनाडु, आन्ध्र, कर्नाटक असम, पंजाब, हरियाणा, जैसे राज्यो मे अभी स्पष्ट विकल्प दिखना शुरू नही हुआ है। यदि जनता ने राहुल गांधी को स्पष्ट नकार दिया और सोनिया गांधी को समझ आ गई कि अब जनता अंध परिवारवाद के पक्ष मे नही है तो मनमोहन सिंह तीसरी पारी भी शुरू कर सकते है। तब संभव है कि पूरे देष मे लोकतंत्र की बयार बहने लग जावे । तब पूरे भारत मे नायक और खलनायको की अलग अलग पहचान आम नागरिक भी तत्काल करने मे संक्षम हो जावे। तब संभव है कि मुझे इस तरह अपनी पूर्व की भविष्य वाणी की याद कराने की जरूरत नहीं पडेगी।

मै आपको एक बात बताना आवष्यक समझता हूँ कि मैने राजनैतिक चरित्र के दो हिस्से नायक और खलनायक के रूप मे किये है। इन दोनो सूचियो मे राहुल गांधी का नाम नही होते हुए भी मै राजनीति मे उनकी स्थापना को सर्वाधिक घातक समझता हूँ । यहॉ तक कि खलनायकों की सूची से भी ज्यादा खतरनाक । प्रष्न राहुल गांधी की योग्यता का नही है बल्कि प्रष्न उस परंपरा को मजबूत करने का है जो नेहरू परिवार स्थापित करना चाहता है। राहुल गांधी स्वतंत्र रूप से योग्यता सिद्ध करते यह भिन्न बात है। किन्तु किसी पार्टी का अध्यक्ष और महासचिव उसे स्थापित करने की कोषिष करे और सफल हो जावे यह बिल्कुल भिन्न । यह तो हम सबके लिये डूब मरने की बात है कि हम स्वयं संचालित न होकर किसी परिवार के प्रचार से संचालित होकर निष्कर्ष निकालते है। यदि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष रहे और प्रधानमंत्री कोई भी और हो जो अध्यक्ष आश्रित न होकर लोकतांत्रिक परिपाटी से बंधा हो तो क्या बिगड जावेगा? सोनिया जी की टीम के कई पत्रकार तक मनमोहन सिंह

की एक पक्षीय आलोचना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी को बढाने के लिये प्रयत्नषील है किन्तु स्पष्ट है कि भारत की जनता अब परिपक्व हो गई है या हो रही है और रही सही कसर हम जैसे लोग पूरी कर रहे है। उत्तर प्रदेष को बपौती समझने वाले राहुल दिग्विजय को जनता ने रास्ता दिखा दिया। अब भी समय है कि सोनिया जी जन भावनाओं का सम्मान करते हुए नेहरू परिवार की बपौती की परंपरा को तोडे , मनमोहन सिंह के साथ तिकडम बन्द करे, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को भंग कर दे तथा दिग्विजय सिंह जैसे चाटुकारो को पार्टी पद से हटा दे तो संभव है कि राहुल गांधी की योग्यता निर्विवाद प्रभावित हो सके अन्यथा यदि सोनिया जी मनमोहन सिंह को बदनाम करके राहुल की ताजपोषी की तिकडम करती रही तो न मनमोहन रहेगे न कांग्रेस और राजनीति का यह अध्याय सोनिया जी लिखित दस्तावेज बन जायगा जो उनके लिये उचित नही होगा।

प्रष्नोत्तर

1.अमर सिंह आर्य, जयपुर, राजस्थान

प्रष्न–कष्मीर समस्या पर सरकार, बुद्धिजीवी और आपके विचारो मे भिन्नता है। कुछ तो काष्मीर को भारत का अंग नही मानते हैं। पृथ्वीराजों पर भी टिप्पणी सटीक है। तक्षषिला नरेष अम्भीक ने पंजाब के राजा पुरू से शत्रुता का बदला लेने हेंतु सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली । जम्मू के राजा विजय देव की मदद से स्याल कोट मे किला बनाया, लाहौर पर सिकन्दर ने कब्जा कर लिया। आज भी सरकार मे और बाहर अनेको अम्भीक विजय देव पृथ्वीराज मौजूद हैं। आपने काष्मीर समस्या का मूल इस्लाम की विस्तार वादी, झगडा पैदा कर थका देने तक की नीति मे निहित माना जो सटीक मालूम होती है, कथनानुसार इस्लाम का पेट काष्मीर से भरने वाला नही। साम्प्रदायिकता को संतुष्ट नही किया जा सकता विषेष कर जब वह आतंकवाद का सहारा लेना शुरू कर दे । उसे कुचलना ही समाधन माना परन्तु हमारे जैसी लचर शासन व्यवस्था मे कुचला जाना संभव नही लगता। समाज के बंटे होने के कारण निपटना दुष्कर है। फिर इसका क्या समाधान हो?

2. सत्ता का केन्द्रीयकरण भ्रष्टाचार का कारण है । अस्सी दषक से पूर्व लिपिक स्तर तक कर्मचारियो की नियुक्तियां जिला स्तर अधिकारी मण्डी समिति व स्वायत शासी निकाय अपने स्तर पर नियुक्तियॉ करते थे कोई पैसा नियुक्तियों मे नही चलता था बाद मे सरकार द्वारा नियुक्तियो की सारी शक्तियां राज्य स्तर पर केन्द्रित करने के बाद भ्रष्टाचार पनपा ।

3. भ्रष्टाचार के विरूद्ध अन्ना आंदोलन हुआ। फिर हिसार चुनाव व पांच राज्यो के चुनावों मे चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस व टीम अन्ना मे बयान बाजी । आपके विचार मे लोक संसद के लिये संघर्ष करना चाहिये। लोक संसद का विचार स्पष्ट समझ मे भी है अथवा नही। ज्ञान तत्व के अंक 237 मे लोक संसद का विचार आया । समाज मे अभी ज्यादा प्रचारित नही है। इसके हिसाब से संसदीय व्यवस्था मे तीन सदस्य 1. लोक सभा 2 राज्यसभा 3 लोक संसद होगे । लोक संसद सदस्यो के लिये वेतन तथा अन्य सुविधाओ को देने की आपकी मान्यता नही है परन्तु जब दो सदनो के सदस्यो के लिये अपार सुविधा तीसरे सदन के सदस्यो को केवल बैठक भत्ता। कैसे चल पायेगा जबकि आज पंचायत सदस्य तक मानदेय चाहते है। लोक सभा के 1/5 सदस्यो के प्रति वर्ष चुनाव का भी सुझाव आया था, ताकि ब्लैक मेल न किया जा सके। राज्य सभा क्षेत्रीय ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिये बनी थी परन्तु यह उद्देष्य समाप्त हो चुका है। सदन दो ही रहे राज्य सभा का स्थान लोक संसद ले पर विचार हो । कार्य विभाजन एवं कानून बनाने की विधि पर विचार आवष्यक । सदनो पर सदस्यो पर किसी भी रूप मे जनता के नियंत्रण का तरीका ढूढा जाना चाहिये। संसद के सदस्यो के वेतन भत्तो सुविधाओ हेतु सदनो के अलावा वेतन आयोग आदि पर विचार होना चाहिये।

सर्वोच्च संसदीय संस्थाए ठीक से कार्य करे । उनके सदस्यो पर समाज के नियंत्रण का प्रावधान बने जिससे संसद के सदनो मे जन प्रतिनिधि सही दिषा मे जनहित मे काम करे। लोक सभा से पंचायत तक एक साथ चुनाव हो। प्रत्याषियो के चयन मे जनता की भागीदारी की व्यवस्था बने चाहे चयन ग्राम सभाओ शहरो मे विधायक व लोक सभा क्षेत्र की वार्ड सभाए बैठक कर आम सहमति या बहुमत जैसी भी व्यवस्था बने तय करे। चुनाव संबंधी सुधारो के कार्यो का संसद के अलावा व्यवस्था बननी चाहिये। ताकि अपराधी सामज विरोधी तत्व चुनाव न लड सके। चुनाव पूर्व ही चार माह पूर्व प्रत्याषी तय हो पार्टी सुप्रीमो की तानाषाही तोडी जाय । । प्रत्याषियो के आपराधिक चरित्र, कर चोरी, धोखाधडी ,अवैध कार्यो की जानकारी पूर्व मे ही इकठ्ठी कर सार्वजनिक की जाये। प्रत्येक प्रत्याषी क्षेत्र की जनता को उसके बारे मे पूरी जानकारी दी जाये ताकि जनता वोट से पूर्व वोट देने का मानस बना सके । सुब्रमणयम स्वामी के तरीके पर आपकी क्या राय है

अमेरिका की तरह सभी संवैधानिक संस्थाओ के चुनाव चार माह पूर्व ही सम्पन्न कर लिया जाये । इस अवधि मे प्रत्याषियो को लोक तांत्रिक प्रणाली का प्रषिक्षण हो तथा पूर्ववर्ती दक्ष प्रतिनिधियो से संसदीय कार्य प्रणाली की जानकारी करायी जाय ताकि कार्य क्षमता बढाने मे मदद मिल सके। जन प्रतिनिधियो का दायित्व सदन के साथ जनता के प्रति स्पष्ट निर्धारत होने चाहिये। हर वर्ष लक्ष्य तय हो तथा कार्यो की समीक्षा की व्यवस्था बने।

उत्तर– आपने कष्मीर समस्या का सम्पूर्ण समाधान जानना चाहा है। मेरे विचार मे इसका समाधान न हिन्दूकरण है न ही पाकिस्तान विरोध । हिन्दू मुसलमान में समाज को बांटना घातक परंपरा है। क्योकि यदि समाज का हिन्दू मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण होगा तो मुसलमान लाभदायक स्थिति मे रहेगा। इस्लाम मूल रूप से संगठन प्रधान होता है और हिन्दू गुण प्रधान। यदि संगठन को आधार बनाकर ध्रुवीकरण होगा तो मुसलमानों को सुविधा होगी क्योकि वे तो मूल रूप से संगठित ही है। यदि सांप्रदायिक तथा धर्म निरपेक्ष के बीच ध्रुवीकरण होगा तो हिन्दू लाभ मे रहेगा और मुसलमान घाटे मे । संघ परिवार ना समझी मे धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करना चाहता है जिसके परिणाम स्वरूप हिन्दू लगातार घाटे मे जा रहा है और भविष्य मे भी जाता ही रहेगा। यदि कष्मीर मामले मे संघ की बात मान ली जावे तो कष्मीर को आधार बनाकर युद्व भी संभव है जिसमे इस्लामिक एक जुटता भी सकती है और उसमे पाकिस्तान का शामिल होना भी संभव है । मेरा सुझाव है कि साम्प्रदायिकता और धर्म निरपेक्षता के बीच ध्रुवीकरण हो जिसमे शान्ति प्रिय हिन्दू मुसलमान इसाई एक साथ हो तथा साम्प्रदायिक हिन्दू मुसलमान इसाई एक साथ। चूंकि मुस्लिम बहुमत साम्प्रदायिकता के साथ होगा तथा हिन्दू बहुमत धर्म निरपेक्षता के साथ इसलिये कष्मीर समस्या का समाधान आसान हो जायगा । मेरा स्पष्ट मत है कि संघ का कष्मीर संबंधी सोच बिल्कुल गलत है तथा इस्लामिक शक्तियो को इससे एकजुट होने मे मदद होती है।

लोक संसद का प्रस्ताव सिर्फ भारत के लिये ही नया नही है बल्कि सम्पूर्ण विष्व के लिये नया है । इसके विचार मंथन के दो भाग है। (1) लोक संसद की आवष्यकता (2) प्रक्रिया । जो लोग लोक संसद की आवष्यकता समझते है उनके साथ तो प्रक्रिया संबंधी चर्चा भी संभव है किन्तु जो लोग इसे आवष्यक ही नही मानते वे यदि प्रक्रिया संबंधी प्रष्न करें तो वे चर्चा योग्य नही । उन्हे पहले लोक संसद की आवष्यकता पर प्रष्न करना चाहिये। आपकी भाषा से ऐसा लगता है कि आप लोक संसद की आवष्यकता से सहमत है। यह विचार अब तक नया होने से कम प्रचारित है फिर भी इस विचार को ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिलने लगा है। जो लोग सत्ता को अपनी व्यक्तिगत क्षमता विस्तार का माध्यम नही बनाना चाहते वे सब लोक संसद विषय पर विचार मंथन मे सक्रिय है। उन्ही मे से एक आप भी है। आपने राज्यसभा की निरर्थकता की बात कही है। मै भी ऐसा ही सोचता हूँ किन्तु यह तो लोक संसद की प्रक्रिया संबंधी चर्चा का भाग है । यदि हम लोक संसद के प्रस्ताव को ज्यादा अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे तो लोक संसद की आवष्यकता के विरोधियों को नये नये बहाने मिलते जायंगे। जो लोग वर्तमान संसदीय लोकतंत्र का लाभ उठा रहे है उन्हे बेदखल करने के लिये न्यूनतम प्रस्ताव ही रखना उचित होगा न कि श्रेष्ठतम । यही कारण है कि मै ने लोक संसद के सदस्यो को वेतन भत्ते से भी किनारे रखा है। वैसे भी लोक सांसद की सक्रियता यदा कदा ही रहेगी।

इसलिये वेतन देना न आवष्यक है न ही उचित । आपने सांसदो के वेतन भत्ते के लिये आयोग की बात की जो अनावष्यक है, क्योकि लोक संसद बनने के बाद वेतन भत्तों का मामला लोक संसद स्वयं देख लेगी।

आपने संसद मे पहुॅच रहे अपराधियों भ्रष्टाचारियों की बढती संख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए नये कानून का सुझाव दिया है । मै आपकी चिन्ता से सहमत हूॅ तथा प्रयत्न के विरूद्ध । संसद मे भ्रष्टाचार करने वालों की संख्या तो अनगिनत है ही किन्तु अपराधियों की संख्या भी बढती ही जा रही है इन्हे रोकने का काम कानून नही कर सकता क्योकि यह कार्य मतदाता ही कर सकते है, कानून नही। आप देख रहे होगें कि पिछले तीन वर्षो से मतदाताओं का ध्यान इधर गया है। अब राजनीति मे अपराधियों की जगह अच्छे लोगों की पूछ परख बढने लगी है । अगले आम चुनाव आते तक और स्पष्ट हो सकेगा। आपने सुव्रमन्यम स्वामी का तरीका बताये बिना मेरी राय मांगी है। आप उनका तरीका पहले बताने की कृपा करे तब सलाह देना संभव है।

आपके अन्य सुझाव भी विचारणीय है जिनपर कभी आगे चर्चा संभव है। एक बात पर मै आप सबसे भिन्न विचार रखता हूॅ कि आप सब लोग अच्छे लोगों को चुनने की वकालत करते रहते है जो मेरी नजर मे फिजूल की कसरत है। पहले संसद के अधिकार कम करिये तब उसमे अच्छे लोगो का प्रवेष संभव होगा। यदि समाज के अधिकार कम करते हुए लगातार राजनेताओ के पास इसी तरह पावर इकठ्ठा होता रहा तो चोर डाकू हत्यारों का आकर्षण रहना स्वाभाविक है। अच्छा हो कि समाज और राज्य के बीच दूरी घटे।

2श्री अंजली कुमार झा, नवोत्थान, लेख सेवा–हिन्दुस्तान समाचार

विचार– अमेरिका सोची समझी रणनीति के तहत परमाणु जांच आयोग के कंधे पर सवारी कर ईरान को भी ईराक भी भांति नेस्तनाबूद करने की फिराक मे है। दांव भले ही उल्टा लगा किन्तु प्रयास वर्षो से जारी रहने का दुष्परिणाम यह हुआ कि अरब देष एक जुट हो रहे है। इससे अमेरिका की रही सही अर्थव्यवस्था और राजनीतिक साख चौपट हो जायेगी। एक ध्रुवीय व्यवस्था अब ढह रही है और द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय व्यवस्था पूर्व की भांति आकार ले रही है। चीन, रूस और भारत महाषक्ति के रूप मे स्वीकार्य ही चुके है । तेल के बहाने पूरे मध्य पूर्व के देषो पर संप्रभुता हासिल करने की अमेरिकी क्षुधा डायनासोर की भांति भयावह है। इराक और अफगानिस्तान के विनाष को हम भूले भी नही कि मिस्त्र, सीरिया के दमनचक्र के कम्पन के साथ रूदन जारी है। लोक तंत्र के नाम पर अमेरिकी शह पर सब कुछ जायज है, ऐसा मानने वाले भारत ने भी पहली बार साफगोई से इरान का समर्थन कर अमेरिकी दादागिरी रोकी । पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खडा कर आतंकवाद फैलाने के घिनौने खेल का पर्दाफाष कई बार हुआ, किन्तु अमेरिका अपने हाथ होने से पाक की भांति इंकार करता रहा। अब अमेरिका को पाकिस्तान की नही, भारत की कहीं ज्यादा आवष्यकता है, इसलिये वह अपनी भूल स्वीकार कर भारत से हर प्रकार की मदद चाहता है। मुस्लिम देष, चीन, रूस अब अमेरिका को खुले तौर पर चुनौती दे रहे है। इसका जबाब देने मे आर्थिक मंदी से कराह रहा अमेरिका अक्षम साबित हो रहा है। ओबामा की चुप्पी सब कुछ बयां कर रहा है। नई दिल्ली तेहरान को नाभिकीय प्रयास संधि की बाध्यताओं से बांधने के अमेरिकी तरीके से असहमत है। अरब देषों की भारत से बडी अपेक्षाये है। तभी तो अमेरिका के राजनीतिक मामलों के पूर्व उप विदेष मंत्री निकोलस बर्न्स ने द डिप्लोमेट मे लिखा, ओबामा और बुष ने कई मौकों पर भारत के साथ सहयोग बढाने के लिये अपनी प्रतिबद्धताऍ जताई लेकिन भारत ने वैसी गर्मजोषी नहीं दिखाई । भारत की विदेषी तेल पर निर्भरता बढकर 10 फीसदी पहुॅच गई है। वह किसी भी कीमत पर ईरान को नहीं खोना चाहता है। भारत की अब इजराइल खुल कर मदद करता है। सीरिया के मसले पर चीन और रूस एक हो गये । भारत की द्विविधा उसे हाषिये पर ला देगी। यूरोप 18 फीसदी जबकि भारत 13 फीसदी कच्चा तेल ईरान से आयात करता है। भारत सर्वाधिक चावल का निर्यात ईरान को करता है।

3श्री अजेय कुमार जनसत्ता नौ दिसम्बर दो हजार ग्यारह

विचार–पिछले दिनों का एक और अमेरिका विरोधी शासक नाटो की गोलियों का षिकार हुआ। दुनिया भर के मीडिया ने कहीं यह खबर नही छापी कि नाटो के हमले मे न केवल कज्जाफी, बल्कि उनका एक पुत्र और तीन पोते भी मारे गए। हां पहली खबर जो इलेक्ट्रानिक मीडिया ने दिखाई वह यह थी कि उनके शव को जूतो से मारा गया, उनके बाल खींचे गए, उनके शरीर को कमर तक तंगा किया गया और उसे मिस्त्रता की गलियों मे घुमाया गया । एक रिर्पोट यह भी छपी कि उनके मृत शरीर को एक ऐसे चलते फिरते रेफ्रिजरेजर मे रख कर घुमाया गया जिसमे आर पार सब दिखाई देता था।

इन सब खबरो का उद्देष्य दुनिया को यह बताना था कि वह इसी लायक था और इसलिये उसका यह हश्र करना लीबिया वासियों के लिये अत्यन्त आवष्यक था। प्रायः सभी अंतरराष्ट्रीय अखबारो, गार्डियन से लेकर डेली टेलीग्राफ तक ने 21 अक्टूबर के अपने संस्करण मे कज्जाफी की हत्या के एक दिन बाद खुषियों का इजहार किया। कुछ सुर्खियां इस तरह थी गंदे सीवर मे कज्जाफी को गोलियों से भूना गया चूहो को स्वादिष्ट भोजन मिला, दयाहीन तानाषाह पर कोई दया नही आदि।

यह सच है कि कज्जाफी कई अन्य तानाषाहों की तरह एक तानाषाह था। 'फाइनेषियल टाइम्स ने, जो प्रायः तर्कषील खबरो के लिये जाना जाता है, कज्जाफी के बारे मे लिखा,' एक ऐसा तानाषाह, जिसने अपनी जनता को गरीब बनाया' । लेकिन यह कहना सरासर झूठ है। संयुक्त राष्ट्र और विष्व बैक की मानव विकास रिर्पोट ने स्वीकार किया है कि पूरे अफ्रीका मे लीबिया मे लोगों का जीवन स्तर सबसे अच्छा है। वहॉ साक्षरता दर पंचानवे प्रतिषत है, औसत जीवन प्रत्याषा या संभावित आयु सत्तर वर्ष से उपर है और प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन 16,500 डॉलर प्रतिवर्ष रहा है।

हर लीबियावासी के लिये षिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सेवाए मुफ्त उपलब्ध है। हर लीबियावासी को शादी के वक्त नया जीवन शुरू करने के लिये पचास हजार डॉलर के बराबर राषि दी जाती है। जो आमदनी लीबिया राष्ट्र को तेल से प्राप्त होती है, उसमे से हर वर्ष पांच हजार डालर हर लीबिया वासी के खाते मे जमा कर दिये जाते है।

कज्जाफी के शासन काल के ये तमाम आंकडे केवल संयुक्त राष्ट्र की मोटी मोटी रिपोर्टो मे कैद होकर रह जाते है , जिन्हे कोई नही पढता । लेकिन द सन जिसे लंदन मे पचास लाख लोग पढते है ने कज्जाफी को दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी, लीबिया का पागल कुत्ता कह डाला और उसकी मौत के लिये ब्रिटेन के बहादुर सिपाहियों की तारीफ की है जो नाटो मे शामिल थे। किसी अखबार ने यह नही लिखा कि लीबिया पर हमले मे केवल कज्जाफी नही, पचास हजार से अधिक नागरिक भी मारे गये।

प्रथम विष्वयुद्ध के समय सौ लोग मारे जाते थे उनमे पंचानवे सैनिक और पांच नागरिक होते थे। आज दस सैनिक मारे जाते है और नब्बे नागरिक । आज नागरिको के साथ साथ अस्पतालो, बिजलीघरो, रेडियो और टेलीविजन प्रसार तंत्रो को भी स्वाहा कर दिया जाता है। जो नागरिक जीवित बच जाते है, उन्हे भी जीवन की बुनियादी सहूलियतों से महीनों तक वंचित रहना पडता है।

आज सवाल यह है कि वर्तमान वैष्विक राजनीतिक परिस्थितियों मे तानाषाह किसे कहा जाए। अमेरिका ने कई तानाषाहों का समर्थन किया है, वह इरान का शाह रहा हो या पाकिस्तान के तमाम फौजी शासक रहे हो। यानी कई तानाषाह तब तक तानाषाह नही है जब तक वह अमेरिका द्वारा निर्धारित शर्तो को मानने से इनकार नही करता। ग्यारह सितम्बर के हमले मे जो अठारह या उन्नीस लोग शामिल थे, उनमे से पंद्रह सउदी अरब से थे और सभी बेहद अमीर परिवारों से संबंधित थे। अमेरिका ने सउदी अरब का बाल भी बांका नही किया। सद्दाम हुसैन अमेरिका के तत्कालीन रक्षा मंत्री रम्सफेल्ड और डिक चेनी का घनिष्ठ मित्र था, पर वह खुमैनी के खिलाफ था, इसलिये अमेरिका ने कुछ देर मित्रता निभाई। जब वह दौर निकल गया तो बदली हुई परिस्थिति मे उसे फांसी पर लटका दिया गया। लीबिया मे अमेरिका ने तमाम आतंकवादी गुटो और पूर्व राजा इदरिस के अनुयायियों की मदद की , सिर्फ इसलिये कि वे कज्जाफी के विरूद्ध थें जो लोग वाइट हाउस या दस डाउनिंग स्ट्रीट मे बैठकर तय करते है कि हमले के लिये किस राष्ट्र का नम्बर कब लगना चाहिये, क्या वे लोग तानाषाह नही है? उन्हे

क्या तानाषाह नही कहेंगे जिन्होने अपनी वेबसाइट पर खुलेआम घोषणा कर रखी है कि कोई भी ऐसा देष पनपने नही दिया जायगा जो अमेरिका को सोवियत संघ जैसी टक्कर दे सके। आप या तो हमारे मित्र है या दुष्मन है, यह रवैया क्या तानाषाही भरा नही है? आज वे यह तय कर रहे है कि अब सीरिया से पहले निपटें या इरान से। इरान के बारे मे मिथ्या अभियान लगभग पूर्वनियोंजित ढंग से चल रहा है।

आज बहस के लिये मुख्य मुद्दा यह होना चाहिये कि क्या चालीस करोड की आबादी वाले मध्य पूर्व मे केवल साठ लाख की आबादी वाले देष इजराइल के पास ही नाभिकीय एकाधिकार होना चाहिये? सिर्फ इसलिये कि अमेरिका और अन्य पष्चिमी ताकतें यही चाहती है। हैरानी की बात यह है कि जब एक आदमी दूसरे आदमी को पांव की जूती समझता है तो अधिकतर व्यक्तिों का खून खौलने लगता है, पर जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को पांव की जूती समझता है तो थोडी फुसफुसाहट के सिवा कुछ नही होता। इस दुनिया मे वे तमाम लोग जो अपने अपने देष से प्यार करते है और अपना भविष्य अपने हाथों से बनाने मे विष्वास करते है, उन्हे मुअम्मर कज्जाफी की वसीयत के इन अंषो को ध्यान से पढना चाहिये। वह वसीयत मंथली रिव्यू के ताजा अंक मे छपी है। इसमे लिखा हैः ''दुनियॉ की आम जनता को हम यह बताना चाहेंगे कि अगर हम चाहते तो हिफाजत और सुकून भरी जिंदगी के बदले अपने पवित्र उद्देष्य के साथ समझौता करके उसे बेच सकते थे। हमे इसके लिये कई प्रस्ताव मिले, लेकिन हमने अपने कर्तब्य और सम्मान पूर्ण पद के अनुसार लडाई के हरावल दस्ते मे रहना पसंद किया। अगर हम तुरंत जीत हासिल न भी कर पाएं तो भी, आने वाली पीढियो को यह सीख दे जाएंगे कि अपनी कौम की हिफाजत करने के बजाय उसे नीलाम कर देना बडी गद्दारी है, जिसे इतिहास हमेषा याद रखेगा, भले ही दूसरे लोग इसकी कोई दूसरी ही कहानी गढते और सुनाते रहे।''
मीडिया द्वारा झूठ के पहाण खडे करने से सच को कुछ देर तक छुपाया जा सकता है, पर दुनिया का अवाम और खुद अमेरिका मे मेहनतकष लोग साम्राज्यवादियों को चैन से नही बैठने देंगे।

उत्तर– अमेरिका विरोध को ढाल बनाकर साम्यवादी इस्लामिक तानाषाही का समर्थन करने वाले आप अकेले व्यक्ति नही है। बडी संख्या मे ऐसे पत्र लेख या विचार आते रहते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से तो अमेरिका के विरूद्ध होते हैं किन्तु परोक्ष रूप से साम्यवादी इस्लामिक तानाषाही के समर्थक। जबसे भारतीय अर्थ व्यवस्था समाजवादी पूंछ छोडकर उदारवादी मार्ग पर चलना शुरू की है तबसे तो ऐसे लेखको विचारकों की बाढ सी ही आ गई है। इसलिये आवष्यक है कि इस विचार की विस्तृत समीक्षा हो।

प्रत्तुत लेख मे अजेय कुमार जी ने अमेरिका की तुलना मे सद्दाम गद्दाफी इरान के पक्ष मे विचार प्रस्तुत किया है। तुलना दो समान विचारधाराओं के बीच ही होती है । अमेरिका मे आन्तरिक लोकतंत्र है और साम्यवादी इस्लामिक देषों मे आंतरिक तानाषाही। अमेरिका मे किसी व्यक्ति का शासन न होकर एक सिस्टम की सरकार है । वहॉ के शासक बदल सकते है सिस्टम नहीं। साम्यवादी इस्लामिक देषों मे व्यक्ति की सरकार भी है और उसी का सिस्टम भी । व्यक्ति आसानी से नही बदल सकता। अमेरिका तानाषाह हो सकता है किन्तु अमेरिका मे तानाषाही न होकर लोकतंत्र है जबकि लीबिया इरान आदि मे आंतरिक तानाषाही है। गद्दाफी के शासन काल मे लोग स्वर्णिम सुख मे जीते थे जैसा कि आपने लिखा है तो हो सकता है कि आपका लिखा सच ही हो किन्तु वे गुलाम थे यह बात भी पूरी तरह सच है। इसलिये आपसे मेरा निवेदन है कि लीबिया इरान आदि तानाषाह देषों से अमेरिका की तुलना करना सीधा सीधा लोकतंत्र के प्रति नासमझी ही मानी जायगी।

अमेरिका तानाषाहों से भी बडा तानाषाह है यह आपका आरोप है। अमेरिका तानाषाहों के प्रति तानाषाह सा व्यवहार करे तो आपको क्यों कष्ट हुआ। अमेरिका ने किसी तानाषाह के प्रति तानाषाही की है, किसी लोकतांत्रिक देष के साथ नही। यह दो तानाषाहों के बीच का आंतरिक व्यवहार है, भारत उसमे लोक तांत्रित देष होने से लोकतंत्र का स्वाभाविक मित्र है। स्वतंत्रता से आज तक अमेरिका ने भारत पर तो आक्रमण नही किया । इसके उलट चीन और पाकिस्तान ने ही भारत पर कई बार आक्रमण किया। चीन और पाकिस्तान के प्रति हमें सतर्कता रखनी होगी। यदि चीन और पाकिस्तान के प्रति अमेरिका सतर्क रहे तो अमेरिका हमारा स्वाभाविक मित्र बना।

मुझे याद है कि पाकिस्तान द्वारा भारत आक्रमण के समय जब अमेरिका ने पी एल चार सौ अस्सी का गेंहु बन्द करने की धमकी दी थी तब पूरा देष अमेरिका के विरूद्ध शास्त्री जी के साथ खडा हो गया था। मै स्वयं भी उस विचार की उपज हूँ । मैने भी शास्त्रिी जी की केला पपीता उगाओ की ललकार के साथ वर्षों काम किया । आज इरान भारत को गैस और तेल बन्द करने की धमकी देता है और भारत उसके समक्ष झुक जाता है। उस समय गेहुँ का सवाल था और आज तेल का है। भोजन पेट के लिये था और तेल सुविधा के लिये। आज हमारी सरकार मजबूती से जबाब दे नही सकती क्योकि उसे भय है कि आप जैसे देष भक्त लोग ऐसे समय मे साथ देंगे या नही। थोडा सा डीजल पेट्रोल का दाम बढाने के प्रस्ताव पर तो आप सरीखे लोग पचास प्रकार का नाटक करना शुरू कर देते हो। यदि हिम्मत के साथ इरान को कुछ कह दिया जाय तो पता नही आपका रूख क्या हो।

अमेरिका परमाणु बम सम्पन्न देष है और इरान बना रहा है। आपका आरोप है कि इरान को भी परमाणु बन बनाने का उतना ही अधिकार है जिनता अमेरिका को। मै सिद्धान्त रूप से आपसे सहमत हूँ । मै यह जानना चाहता हूँ कि किसी लोकतांत्रिक देष के पास बम होने और किसी तानाषाह के पास बम होने मे कोई अंतर नही है क्या? आज अमेरिका पूरी दुनिया मे सबसे ज्यादा शक्तिषाली है। पूरी दुनियॉ उससे डरती है। यदि अमेरिका की जगह इरान या गद्दाफी या सद्दाम सरीखा देष या तानाषाह अमेरिका के समान एक पक्षीय शक्ति सम्पन्न रहा होता तो दुनिया का क्या हाल होता? निष्चित रूप से अमेरिका की अपेक्षा पूरी दुनियॉ मे भय अधिक होता। अमेरिका के पास बम है। इसका उत्तर यह नही है कि सबके पास बम हो । इसका उत्तर तो यह है कि सब मिलकर परमाणु बम सम्पन्न राष्टो को भी बम नष्ट करने हेतु तैयार करें। दुनिया मे जब तक तानाषाह रहेंगे तब तक अमेरिका के पास यह बहाना है कि साम्यवादी इस्लामिक तानाषाहों के विरूद्ध अमेरिका रक्षा कवच है। आप जैसे लेखक अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की मदद कर रहे है। एक बार दुनिया को तानाषाहो से मुक्त हो जाने दीजिये । फिर तो लोकतांत्रिक देष अमेकिा से भी मुक्त हो जायगे। किन्तु जब तक तानाषाहो का खतरा खतम नही होता तब तक आपके लेख बेअसर ही होंगे।

आपने उसी इरान के पक्ष मे आवाज लगाई है जिसने भारत मे आकर कहा कि इजराइली दूतावास कर्मचारी पर हुआ आक्रमण इजराइ ने ही इरान को बदनाम करते के लिये कराया है। उस समय भी आप जैसे लेखकों ने इरान का पक्ष लिया था अब पूरा मामला साफ होने के बाद आप जैसे लोगो की लेखनी इस विषय पर चुप है। उस समय एक साधारण व्यक्ति भी समझता था कि इरान झूठ बोल रहा है किन्तु आप इजराइल अमेरिका विरोधी इतनी स्पष्ट झूठ को भी नही समझ पा रहे थे।

अमेरिका भारत का प्रतिद्वंदी है । अमेरिका पूरी दुनियॉ का एक छत्र मुखिया बनना चाहता है। उसकी योजना खतरनाक है। अमेरिका के पास अथाह धन भी है और चालाक तिकडम भी। अमेरिका का मुकाबला सिर्फ भारतीय विचार धारा ही कर सकती है जिसके पास बौद्धिक ताकत तो अमेरिका से कई गुना ज्यादा है किन्तु शारीरिक या आर्थिक शक्ति बहुत कम। साम्यवादी इस्लामिक संघ परिवार से जुडे लोग अमेरिका को बौद्धिक स्तर पर पछाडने की अपेक्षा शारीरिक स्तर पर पछाडना चाहते है जो संभव नहीं। जब जक साम्यवादी इस्लामिक कटटरवादी हिन्दू ताकते अमेरिका को गाली दे देकर संगठन शक्ति का समर्थन करती रहेंगे तब तक अमेरिका मजबूत से मजबूत होता जायगा। जिस दिन से हम अमेरिका का विरोध रोककर उसके साथ प्रतियोगिता मे उतर जायेगे उसी दिन से हम ठीक राह पर चलने लगेंगे। मुझे तो यहॉ तक जानकारी मिली है कि अमेरिकी मित्र देष इतने चालाक है कि वे कई लोगो को गुप्त धन दे देकर साम्यवाद इस्लामिक तानाषाही के पक्ष तथा अमेरिका के विरूद्ध कुछ न कुछ आवाज उठवाते रहते है। जिससे लोकतंत्र विरूद्ध तानाषाही का टकराव रास्ता बदलकर लोकतंत्र विरूद्ध लोक स्वराज्य न बन जावे। मुझे अमेरिका विरोधी तर्क देने वालो के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी।

अपनो से अपनी बात

पिछले लम्बे अनुभव तथा इस वर्ष की दो माह की यात्रा के बाद मै अपने मित्रो तथा समर्थको को यह संदेष देना चाहता हूॅ कि हम सबकी कुछ गंभीर दिषा स्पष्ट होनी चाहिये । लोक स्वराज्य हमारा अन्तिम लक्ष्य है। लोक स्वराज्य का अर्थ है भारतीय संविधान मे व्यक्ति, परिवार, गांव, जिला, प्रदेष, राष्ट्र तथा सरकार को पृथक पृथक इकाइयां मानकर उनके अधिकारों की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमाऍ निर्धारित करना। जब तक संविधान व्यक्ति से सरकार तक की सातों इकाइयों की अलग अलग संवैधानिक स्वतंत्रता निष्चित नही करता तब तक हमारा प्रयत्न जारी रहेगा। समाज मे स्पष्ट संदेष जाना चाहिये कि संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र मे बदलना ही लोक स्वराज्य है। यह हमारा लक्ष्य है और हम इस सीमा तक अपने प्रयत्न जारी रखेंगे।

हमारे विचार मे उक्त लक्ष्य की दिषा मे बढने मे लोक संसद तथा ग्राम सभा सषक्तिकरण बहुत उपयोगी होगे। इस दिषा मे जो भी प्रयत्न होगे उनमे हम सबकी सहभागिता होनी चाहिये। वैसे लोक स्वराज्य मंच तथा ग्राम सभा सषक्तिकरण अभियान इस दिषा मे बहुत ठीक कार्यरत है। हम सबकी उसमे सहभागिता है।

अन्ना हजारे की टीम भी आंषिक रूप से इस दिषा मे बढ रही है। इस टीम के प्रमुख सदस्य अरविन्द केजरीवाल प्रषान्त भूषण मनीष सिसोदिया लोक स्वराज्य की लाइन पर विष्वास करते है। हो सकता है कि देष काल परिस्थिति के अनुसार वे धीरे धीरे बढना चाहते हो अथवा उनका मार्ग हमारे मार्ग से कुछ भिन्न भी हो किन्तु मै आष्वस्त हूॅ कि उनकी लाइन ठीक है। हमारा कर्तब्य है कि हम टीम अन्ना का पूरा पूरा समर्थन तथा सहयोग करे। रामदेव जी की लाइन लोक स्वराज्य की नही है । बल्कि ऐसा लगता है कि रामदेव जी सत्तामोह की बीमारी के मरीज है। श्री रविषंकर जी आदि भी साफ नही है फिर भी वे कोई गलत नही कर रहे । जो भी कर रहे है वह कुल मिलाकर ठीक ही है। हमे चाहिये कि हम रामदेव जी या रविषंकर जी सरीखे लोगो के कार्यो की गुण दोष के आधार पर समीक्षा करके अच्छे कार्यो का समर्थन करे तथा गल्तियो के मामले मे सुझाव दे या चुप रहे, विरोध न करे। यद्यपि मुझे पूरा विष्वास है कि रामदेच जी जो भी करेंगे वह लोक स्वराज्य आंदोलन के लिये हानिकर ही होगा फिर भी धैर्य और प्रतीक्षा करनी ही उचित है। ६

इन सबके साथ–साथ चौथी स्थिति भी संभव है कि वर्तमान संसदीय लोकतंत्र मे ही कुछ लोग बहुत अच्छी नीयत के और कुछ बुरी नीयत के दिखते हैं । हमारा कर्तब्य है कि हम अच्छी नीयत और बुरी नीयत वालो की अलग अलग श्रेणी बनाकर अच्छों का मनोबल बढाते रहें तथा खलनायको का गिराते रहें। वैसे वर्तमान राजनेताओ मे प्रधानमंत्री पद के लिये सर्वाधिक इमानदार और योग्य मे तीन नाम दिखते है । 1 मनमोहन सिंहजी 2 नरेन्द्र मोदी जी 3 नीतिष कुमार जी इनकी नीयत और नीतियॉ ठीक ठाक है। इनमे भी नरेन्द्र मोदी कुछ तानाषाही प्रवृत्ति के है तथा अन्य दो की अपेक्षा अधिक दांवपेच वाले है। इसलिये वे समस्याओ का समाधान जल्दी कर सकते है । शान्त प्रवृत्ति वालो मे मनमोहन सिंह नीतिष कुमार है ही। यदि बाहर के लोगों पर विचार करें तो अब तक के अनुभव के आधार पर प्रधानमंत्री के लिये सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति अरविन्दकेजरीवाल दिखते है। मै अभी अभी पांच दिन तक उनके साथ एक कमरे मे रहकर चुपचाप जो अध्ययन किया उस आधार पर मै इस नतीजे पर पहुॅचा हूॅ। यदि कभी प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार नेताओ के हाथ से निकलकर जनता के हाथ आवे तो अरविन्द जी पर विष्वास किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियो मे भी प्रधानमंत्री पद के योग्य व्यक्ति आई पी एस रणवीर शर्मा को मानता रहा हूॅ जो वर्तमान मे हरियाणा मे आई जी पुलिस के पद पर कार्यरत हैं। इस तरह हम सबका कर्तब्य है कि राजनीति से बाहर के लोगों के लिये भी वातावरण बनते रहना चाहिये।

इन सबके साथ साथ हमे अपना मानसिक व्यायाम भी जारी रखना है। यह व्यायाम ही आपको सही समय पर सही निर्णय करने की शक्ति देगा। ज्ञान तत्व पढना, शनिवार शाम आठ बजे ए टू जेड टी वी चैनल देखना काष इन्डिया डाट काम पढना विभिन्न विषयो पर आपस मे विचार मंथन आदि इसमे बहुत सहायक होंगे। मानसिक व्यायाम के लिये मेरे लिखे के विरूद्ध भी लिखने की आदत डालिये।

वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था बुद्धिजीवियों पूंजीपतियों राजनेताओ शहरियों द्वारा श्रमजीवियों गरीबो ग्रामीणो तथा सामान्य लोगों को गुलाम बनाकर रखने का मिला जुला षडयंत्र है। इस षडयंत्र से हम न टकरा सकते है न विरोध कर सकते है । किन्तु हम इस षणयंत्र को उजागर तो अवष्य कर सकते है । गुलाम बनाकर रखने वालो का अपराधी तत्वो से भी गुप्त समझौता है । हम ऐसे षणयंत्र के चंगुल से स्वयं को बचा ले यह भी एक विषेष बात होगी।

पंद्रह सितम्बर से तेइस सितम्बर तक इन सभी मुद्दो पर अलग अलग तथा एक साथ चर्चा होगी । आप ज्यादा से ज्यादा संख्या मे आने की कृपा करे।

आपका

बजरंग मुनि